5.7 नियोजन की आवश्यकता

आज हम सभी नियोजक है । क्योंकि नियोजन आज के युग की एक महौषध (grand panacea) है । यह वर्तमान युग के कलयाणकारी राज्य (welfare state) की स्थापना का एक कारगर उपाय है। यह राज्य या देश के समस्त नागरिकों को एक न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। फलत: नियोजन आज विश्व के सभी देशों में न कवल परमावश्यक वरन् आदरसूचक एवं फैशनेबुल भी हो गया है। विभिन्न देशों में इसकी आवश्यकता के निम्नलिखित कारण है :

5.7.1. पूँजीवादी अर्थव्यवस्थ की बुराईयों का निवारक–नियोजन किसी भी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियायें बाजार प्रणाली द्वारा संचालित होने के कारण इसमे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ सन्निहित रहती है । यह बात कुछ हद तक ठीक है, जैसा कि पूँजीवाद के समर्थक बतलाते हैं कि इस अर्थव्यवस्था मे विभिन्न वस्तुओं के एवं सेवाओं के उत्पादन तथा उनके उत्पदक साधनों के बाजारों में सैद्धान्तिक रूप स पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियां के कारण दीर्घकाल में बाजार या कीमत प्रणाली स दश क समस्त उत्पादक साधनों का सर्वोत्तम आवंटन स्वत: होता रहता है । जिससे दीर्घकाल में बाजार या कीमत प्रणाली से देश के समस्त उत्पादक साधनों का सर्वोत्तम आवंटन स्वत: होता रहता है । जिससे दीर्घकाल मे अधिकतम उत्पादन पूर्ण रोजगार तथा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का न्यायोचित वितरण होता रहता है, जिससे लोगों को स्वतन्त्रता एवं उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता (Consumer's sovereignty) बनी रहती है। परन्तु वास्तविक अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की सारी शर्ते पूरी नहीं हो पाती हैं जिसके फलस्वरूप कीमत प्रणाली द्वारा उत्पदक संसाधनों का सर्वोतम आवंटन, वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकतम उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का न्यायोचित वितरण नहीं हो पाता है । फलत: लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वत: नहीं होता है। इसके अलावे, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों की विभिन्न प्रकार के उत्पादन होने से अधिक आय वर्ग के लोगों की माँगों की पूर्ति भी नहीं हो पाती है । इस कारण पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को आय प्राप्त करने की, उपभोग करने की, बचत एवं विनियोग करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती है और सभी सामान्य उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता नहीं रहती है। इस अर्थव्यवस्था में सामान्यत: अल्पसंख्यक अधिक आय वर्ग के लोगों के देश के समस्त साधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण रहता है। फलत: उनकी ही आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतन्त्रता बनी रहती है और उन माँगों के अनुरूप ही देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, उपभोग विनियम एवं वितरण होता है। उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अधिक उत्पादन, आय बचत, विनियोग करने की उत्प्रेरणा (Incentives) तथा उनकी ही सार्वभौकिता बनी रहती है। इन सबों के अलावे भी, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में स्वत: तेजी एवं मंदी की स्थितियाँ उतपन्न होती रहती है जिसके घातक परिणमा सभी लोगों को भुगतने पड़ते हैं और अर्थव्यवस्था के विकास दर में स्थिरता का अभाव पाया जाात है। नियोजन पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की उपरोक्त सभी बुराइयों, दोषों एवं कठिनाइयों को दूर करने का कम करने का एक कारगर उपाय है

Scanned with CamScanner

(2) उत्पादक साधनो के सर्वोत्तम आवंटन के लिए–नियोजन की आश्यकता किसी अर्थव्यवस्था में इसके समस्त उत्पादक संसाधनों के अधिकतम उपयोग या सर्वोतम उपयोग के लिये भी होती है। नियोजन म किसी भी अर्थव्यवस्था में देश के समस्त उत्पाद साधनों को देश के लोगों की आवश्यकतानुसार वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगाने का प्रयास किया जात है। इसके लिये नियोजन की प्राथमिकताओं के अनुरूप के संसाधनों का आवंटन किया जाता है जिसमें समस्त संसाधनों का सर्वोतम उपयोग होता है ।

(3) पूर्ण रोजगार की अवस्था की प्राप्ति के लिए–नियोजन की आवश्यकता किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की अवस्था की प्राप्ति के लिए भी आज विश्व के प्राय: सभी देशों में कम या अधिक बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है । नियोजित अर्थव्यवस्था में देश की कुल श्रमशक्ति का उपयोग करने के लिए तदनुरूप योजनायों एवं कार्यक्रम बनाये जाते हैं जिससे दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो सके। स्वतंत्र साज श्रम शक्ति का उपयोग एवं पूर्ण रोजगार की प्राप्ति अति दीर्घकाल में भी नहीं हो पाती है। अत: दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए भी नियोजन परमावश्यक है ।

(4) न्यायोचित वितरण व्यवस्था के लिए–नियोजन की आवश्यकता न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है, वरन् इन उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के न्यायोचित वितरण के लिए भी होती है । किसी नियोजित अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकतानुसार (from each according to hiscapacity to each according to his needs) होने के कारण इस व्यवस्था में वितरण न्यायोचित होता है, या कम से कम इस अवस्था में वितरण न्यूनतम होती है । फलत: नियोजित अर्थव्यवस्था में एकाधिकारों की अवस्था की प्राप्ति देश में उत्पादक साधनो का कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में संकेन्द्रण इत्यादि की समस्याएँ भी न्यूनतम होती है ।

(5) न्यूनतम व्यापार-चक्रीय परिवर्तन–किसी अर्थव्यवस्था नियोजन की आवश्यकता देश में विभिन्न कारणों से उत्पन्न आर्थिक उतार-चढ़ाव जिन्हें व्यापर चक्रीय परिवर्तन कहा जाता है, को कम या न्यूनतम करने के लिये भी होता है। किसी नियोजित अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की मौद्रिक वित्तीय व्यापारिक एवं अन्य नीतियों द्वारा देश में अनावश्यक उतारचढ़ावों का कम करने का प्रयास किया जाता है। जो बाजार प्रणाली वाली स्वतन्त्रता व्यवस्था में स्वत: नहीं होता है ।

(6) नव-स्वतन्त्र कम विकसित देशों की समस्याओं के समाधान के लिए–नियोजन की आवश्यकता न केवल विकसित अनियोजित अर्थव्यवस्था की आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के या दूर करने के लिए होती है, वरन् इसकी और अधिक आवश्यकता नव-स्वतन्त्र कम विकसित देशों की मौलिक आर्थिक समस्याओं के लिये भी हो है। इन देशों की प्रमुख समस्याओं के समाधान द्वारा तेजी से आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए या इसे तेज करने के लिए आर्थिक नियोजन अनिवार्य है, क्योंकि इन देशों की सर्वप्रमुख समस्या आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की है, जिसे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में

Scanned with CamScanner

जतो से वृद्धि की जा सके । इस आर्थिक विकास कहा जाता है जो विकसित देशों की सर्वप्रमुख समस्या आर्थिक स्थायितव या आर्थिक विकास की दर को बनाये रखने से है, जिसे आर्थिक वर्द्धन (economic growth) कहा जाता है। अर्थात् विकसित देशों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने तथा उसे तेज करने के लिए या आर्थिक विकास के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए इन देशों में जनसंख्या नियंत्रण, पूँजी निर्माण, शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था इत्यादि के अलावे तेजी से औद्योगिकीकरण द्वारा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में संरचनात्क परिवर्तन (sectoral transformation) की आवश्यकता है, जो बाजार प्रणाली या कीमत प्रणाली द्वारा स्वत: नहीं होता है। न तो भूतकाल में ऐसा स्वत: हो पाया और न ही भविष्य में स्वत: होने की संभावना है। अत: कम विकसित नव-स्वतन्त्र देशों में तेजी से आर्थिक विकास के लिए विकसित देशों की तुलना में नियोजन अधिक आवश्यक है ।

परन्तु इन देशों में विशेष कठिनाई यह है कि विकसित देशों की तुलना में इन देशों के नियोजित विकास की पद्धति अपनाना अधिक कठिन है। इन देशों में भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की कमी, विदेशी मुद्रा की कमी, वैज्ञानिक एवं तकनीकों की उपलब्धता में कमी, अशिक्षित जनसंख्या, दोषपूर्ण प्रशासनिक व्ययवस्था, उद्यम की न्यूनतम इत्यादि की समस्या बड़े पैमान पर पायी जाती है जिनके कारण विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए आवश्यक तथ्यों एवं आंकड़ों का चयन करने उनका सम्पादन करने एवं विश्लेषण करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ होती है । फलत: विकसित देशों की तुलना में अविकसित देशों में नियोजन की अनिवार्यता अधिक होने के बावजूद इन देशों में नियोजन करना विकसित देशों की तुलना में अधिक कठिन है, जैसा कि प्रो० लिविस ने लिखा है– Planning is at the sme time much more necessary and much more difficult in under developed countries than in developed countries.)

5.8 नियोजन के प्रमुख दोष :

विकसित तथा अविकसित दोनों प्रकार के देशों में स्वतन्त्र बाजार प्रणाली की तुलना में नियोजन की श्रेष्ठता के बावजूद नियोजन में विभिन्न प्रकार के दोष भी पाये जाते हैं । अर्थात् नियोजित व्यवस्था पूर्णरूपेण दोष रहित व्यवस्था नहीं होती है । इस व्यवस्था में भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ होती है और इसमें भी विभिन्न प्रकार के दोष पाये जाते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं :

नियोजन का सर्वप्रमुख दोष यह है कि किसी भी नियोजित अर्थव्यवस्था में लोगों की विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं (individual freedoms) का हनन होता है। उदाहरण के लिए इस व्यवस्थ में लोगों को आय प्राप्त करने, प्राप्त आय से आवश्यकतानुसार उपभोग करने या बचत करने तथा बचत को इच्छानुसार विभिन्न कार्यों में विनियोजित करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती है ।

नियोजन का दूसरा दोष यह है कि इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की स्वतन्त्रों की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की माँगों के अनुरूप नहीं होता है। अत: नियोजन में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता नहीं रहती है ।

Scanned with CamScanner

नियोजन का तीसरा दोष यह है कि किसी नियोजित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं की कमी, उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अभाव इत्यादि के कारण लोगों को प्राप्त आय से बचत करने तथा बचत को उत्पादक कार्यों में विनियोजित करने, अधिक आय प्राप्त करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती है, जिसके कारण लोगों को अधिक कार्य करने अधिक आय प्राप्त करने, अधिक बचत एवं विनियोग करने की उत्प्रेरणाओं (Incentives) का अभाव पाया जाता है ।

नियोजन का एक चौथा दोष यह है कि इसमें योजना के विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने, उनकी समीक्षा करने तथा उनके कार्यान्वयन करने में योजनाधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का बोलबाला हो जाता है, जिसके कारण सम्पूर्ण नियोजित प्रक्रिया में कदाचार, भष्टाचार एवं लालफीताशाही उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण देश के संसाधनों की उत्पादन-क्षमता कम हो जाती है, संसाधनों का सर्वोतम आवंटन एंव उपयोग नहीं होता है और उत्पादन अधिकतम संभावित उत्पादन से कम ही होता है ।

नियोजन का एक अन्य दोष यह है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में उपरोक्त कारणों से तथा सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाने के कारण अन्ततः इस व्यवस्था में तानाशाही के पनपने तथा जनतंत्र की समाप्ति का खतरा उत्पन्न हो जाता है। फलतःप्रो० हेबेक ने नियोजन को गुलामी का रास्ता (Road toserfdom) कहा है । इसमें आम लोगों की सत्ता में तथा आर्थिक नियोजन एवं निर्णयों में भागीदारी (peoples participation in economic planning and policy decisions) कम हो जाती है या समाप्त हो जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण नियोजित आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है ।

नियोजन में उपरोक्त दोनों की संभावना है, परन्तु यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि नियोजन या नियोजित विकास की प्रणाली स्वतंत्र, पूँजीवादी बाजार प्रणाली या कीमत प्रणाली से अधिक खराब है। वास्तव में, नियोजन या नियोजित प्रणाली ही स्वतन्त्र बाजार प्रणाली से श्रेष्ठ या बेहतर है। इसमें उपरोक्त दोष योजनाओं को सही ढंग से निर्माण नहीं करने या कार्यान्वयन नहीं करने के कारण उत्पन्न होने की संभावना है। यदि किसी देश में योजनाधिकारी निष्ठावान हैं, वे अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग हैं और देश की जनसंख्या शिक्षित हैं तो नियोजन में उत्पन्न होने वाले उपरोक्त दोषों की संख्या स्वतःकम हो जायगी । जैसे-जैसे देश की जनसंख्या अधिक शिक्षित होगी और अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सजग होगी उनकी योजनाओं को तैयार करने एवं कार्यान्वयन करने की जिम्मेवारी तथा सत्ता में भागीदारी स्वतः बढ़ती जायेगी जिससे नियोजित विकास के लाभों की प्राप्ति होगी और उनके रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होगी । प्रो० लिविस ने भी लिखा है कि नियोजन मे जनसाधारण की भागीदारी नियोजन के लिये मशीनों में दिये जानेवाले लुब्रिकेटिंग वायल (lubricating oil) तथा नियोजित आर्थिक विकास के लिए पेट्रोल का काम करती है जिसके फलस्वरूप उत्पन्न तिशीलता से योजना के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है ।

Scanned with CamScanner